



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 783]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 2012/वैशाख 10, 1934

No. 783]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 2012/VAISAKHA 10, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

का.आ. 942(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (47) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदृश होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 27 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" धारा 10 के खंड (47) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए अवसंरचना ऋण निधि स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश ।

2च. (1) अवसंरचना ऋण निधि की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तारीख 21 नवंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस 233/सीजीएम (यूएस)-2011 अवसंरचना विकास निधि, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां (रिजर्व बैंक) निवेश 2011 द्वारा उपबंधित शर्तों को पूरा करते हुए गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी के रूप में की जाएगी।

(2) अवसंरचना ऋण निधि की निधियों का विनिधान लोक प्राइवेट सह-भागिता अवसंरचना परियोजनाओं और उन तारीख पश्च प्रचालन प्रारंभ अवसंरचना परियोजनाओं में जिन्होंने वाणिज्यिक प्रचालन का कम से कम एक वर्ष समाधानप्रद रूप से पूरा कर लिया है और जिनमें ऐसी अवसंरचना ऋण निधि रियायतग्राही तथा परियोजना प्राधिकारी के साथ संदर्भ के अनिवार्य क्रय और समाप्ति का सुनिश्चय करने के लिए त्रिपक्षीय करार में एक पक्षकार है, किया जाएगा।

(3) अवसंरचना ऋण निधि भारतीय रिजर्व बैंक (आखीआई) के निवेशों के अनुसार और समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या जारी करना) नियम 2000 के सुसंगत विनियमों के अधीन रूपए के अभिदान में या विदेशी मुद्रा में बंधपत्र जारी करेगी।

(4) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा जारी किसी बंधपत्र के निबंधन और शर्ते भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निदेशों और उप-नियम (3) में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होंगी ।

(5) पूर्वोक्त बंधपत्र में किसी विनिधानकर्ता के अनिवासी होने की दशा में ऐसे अनिवासी विनिधानकर्ता के पहले विनिधान के समय बंधपत्र की मूल या आरंभिक परिपक्वता पांच वर्षों से अन्यून अवधि के लिए नहीं होगी ।

परंतु किसी अनिवासी विनिधानकर्ता द्वारा ऐसे बंधपत्रों में किया गया विनिधान तीन वर्षों से अन्यून अवधि की परिवद्ध अवधि की शर्त के अधीन होगा, किंतु अनिवासी विनिधानकर्ता बंधपत्र को ऐसी परिवद्ध अवधि के भीतर किसी अन्य अनिवासी विनिधानकर्ता को अंतरित कर सकेगा ।

(6) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा किसी व्यष्टिक परियोजना या किसी समूह से संबंध रखने वाली परियोजना में किया गया विनिधान किसी भी समय निधि के समग्र के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(7) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा कोई विनिधान नहीं किया जाएगा जहां उसके प्रायोजक या सहबद्ध उद्यम या ऐसे प्रायोजक के समूह का उसमें सारवान् हित है ।

(8) अवसंरचना ऋण निधि धारा 139 की उपधारा (4ग) द्वारा यथाअपेक्षित अपनी विवरणी सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व फाइल करेगी ।

(9) अवसंरचना ऋण निधि द्वारा इस नियम में उपबंधित किसी शर्त या भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों की अननुपालना की दशा में अधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानों कि ये अधिनियम की धारा 10 के उपर्युक्त (47) में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि नहीं है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए -

(i) "सहबद्ध उद्यम" का वही अर्थ है जो उसका अधिनियम की धारा 92क में है ;

(ii) "समुत्थान" का वही अर्थ है जो उसका अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (22) के स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) में है ;

(iii) क्रमशः "रियायतग्राही", "त्रिपक्षीय करार" और "परियोजना प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो उनका अवसंरचना ऋण निधि - गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011 में है ;

(iv) "समग्र" से विनिधान के प्रयोजन के लिए इकट्ठा की गई अवसंरचना ऋण निधि की कुल निधियां अभिप्रेत हैं ;

(v) "समूह" से भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड (पारंपरिक निधियां) विनियम, 1996 की धारा 2 के खंड (ङड) में यथापरिभाषित समूह अभिप्रेत है ;

(vi) किसी व्यक्ति का निम्नलिखित में सारवान् हित रखना समझा जाएगा -

(क) कोई कंपनी यदि वह (जिसमें किसी व्यक्ति के व्यष्टि होने की दशा में उसके एक या अधिक नातेदारों द्वारा धृत फायदाग्राही स्वामित्व सम्मिलित है) शेयरों (ऐसे शेयरों से भिन्न जो लाभ में भाग लेने के अधिकार सहित या उसके बिना लाभांश की नियत दर के लिए पात्र है) जो मत देने की शक्ति का 10 प्रतिशत से अधिक धारण करता है, का फायदाग्राही स्वामी है ; या

(ख) किसी कंपनी से भिन्न कोई समुत्थान यदि पूर्ववर्ती वर्ष में किसी भी समय ऐसे समुत्थान की 20 प्रतिशत से अन्यून आय का पात्र था ।

(vii) "नातेदार" से किसी व्यष्टि के संबंध में अभिप्रेत है -

(क) व्यष्टि का पति या पत्नी ;

(ख) व्यष्टि का भाई या बहन ;

(ग) व्यष्टि के पति या पत्नी का भाई या बहन ;

(घ) व्यष्टि के माता-पिता में से किसी का भाई या बहन ;

(ङ) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या पारंपरिक वंशज ;

- (च) व्यस्ति के पति या पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या पारंपरिक वंशज ;
- (छ) उपर्युक्त (ख) से उपर्युक्त (च) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का पति या पत्नी ; या
- (ज) व्यस्ति या व्यस्ति के पति या पत्नी या भाई या बहन का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या पारंपरिक वंशज ;
- (8) "प्रायोजक" से कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई बैंक अभिप्रेत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार अवसंरचना ऋण निधि के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति किया गया है ।"

[अधिसूचना सं. 16/2012/एफ. 149/72/2011-एसओ (टीपीएल)]

विवेक आनंद ओझा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपर्युक्त (i) में का.आ. 969 तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2012 अधिसूचना सं. का.आ. 694 (अ) तारीख 30-3-2012 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2012

S.O. 942(E).—In exercise of the powers conferred by clause (47) of section 10 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1). These rules may be called the Income-tax (5th Amendment) Rules, 2012.
(2). They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 2E, the following rule shall be inserted, namely:-

"Guidelines for setting up an Infrastructure Debt Fund for the purpose of exemption under clause (47) of section 10.

2F. (1) The Infrastructure Debt Fund shall be set up as a Non-Banking Financial Company conforming to and satisfying the conditions provided by the Reserve Bank of India in the Infrastructure Development Fund – Non Banking Financial Companies (Reserve

Bank) Directions, 2011, vide notification No. DNBS.233/CGM (US)-2011, dated the 21st November, 2011.

- (2) The funds of Infrastructure Debt Fund shall be invested only in the Public Private Partnership Infrastructure Projects and Post Commencement Operation Date Infrastructure Projects which have completed at least one year of satisfactory commercial operation and such Infrastructure Debt Fund is a party to tripartite agreement with the concessionaire and the project authority for ensuring compulsory buy out and termination payment.
- (3) The Infrastructure Debt Fund shall issue rupee denominated bonds or foreign currency bonds in accordance with the directions of Reserve Bank of India (RBI) and the relevant regulations under the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of security by a person resident outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time.
- (4) The terms and conditions of any bond issued by the Infrastructure Debt Fund shall be in accordance with the said directions of the Reserve Bank of India and the regulations referred to in sub-rule (3).
- (5) In case of an investor in the aforesaid bond being a non-resident, the original or initial maturity of bond, at time of first investment by such non-resident investor, shall not be less than a period of five years.

Provided that the investment made by a non-resident investor in such bonds shall be subject to a lock in period of not less than three

years, but the non-resident investor may transfer the bond to another non-resident investor within such lock in period.

- (6) The investment made by the Infrastructure Debt Fund in an individual project or project belonging to a group at any time, shall not exceed twenty percent, of the corpus of the fund.
- (7) No investment shall be made by the Infrastructure Debt Fund in any project where its sponsor or the associate enterprise or the group of such sponsor has a substantial interest.
- (8) The Infrastructure Debt Fund shall file its return of income as required by sub-section (4C) of section 139 on or before the due date.
- (9) In case the Infrastructure Debt Fund does not fulfill any of the conditions provided in this rule or directions of the Reserve Bank of India, all provisions of the Act shall apply as if it is not an Infrastructure Debt Fund referred to in clause (47) of section 10 of the Act.

Explanation.- For the purpose of this rule,-

- (i) "associate enterprise" shall have the same meaning as assigned to it in section 92A of the Act;
- (ii) "concern" shall have the same meaning as in clause (a) of Explanation 3 of sub-section (22) of section 2 of the Act;

1521 97/12-2

(iii) "concessionaire", "tripartite agreement" and "project authority" respectively shall have the same meaning as assigned to them in the Infrastructure Debt Fund-Non-Banking Financial Company (Reserve Bank) Directions, 2011;

(iv) "corpus" means the total funds of the Infrastructure Debt Fund raised for the purpose of investment;

(v) "group" means a group as defined in clause (mm) of section 2 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.

(vi) a person shall be deemed to have substantial interest in –

- (a) a company if he is the beneficial owner (including beneficial ownership held by one or more of his relatives, in case the person is an individual) of shares (not being the shares entitled to a fixed rate of dividend whether with or without a right to participate in profits) holding not less than 10 percent of the voting power; or
- (b) a concern other than a company if he is, at any time during the previous year, beneficially entitled to not less than 20 percent of the income of such concern.

(vii) "relative", in relation to an individual, means—

- (a) spouse of the individual;
- (b) brother or sister of the individual;
- (c) brother or sister of the spouse of the individual;
- (d) brother or sister of either of the parents of the individual;
- (e) any lineal ascendant or descendant of the individual;

- (f) any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual;
- (g) spouse of the persons referred to in sub-clauses (b) to (f); or
- (h) any lineal descendant of a brother or sister of either the individual or of the spouse of the individual;

(viii) "sponsor" means a non-banking financial company, or a bank which is allowed to act as sponsor of Infrastructure Debt Fund in accordance with the directions of Reserve Bank of India."

[Notification No. 16/2012/F. No. 149/72/2011-SO (TPL)]

VIVEK ANAND OJHA, Under Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.O. 969, dated the 26th March, 1962 and was last amended by Income-tax (4th Amendment) Rules, 2012 vide Notification S.O. No. 694(E) dated 30-3-2012.